सिविल अपील

न्यायमूर्ति सोढ़ी के समक्ष

खजान सिंह और अन्य - अपीलकर्ता।

बनाम

दलीप सिंह और अन्य, - प्रतिवादी।

1959 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 304।

3 अक्टूबर 1968.

पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम (एक्स) 1953)-अनुभाग 18-सहायक कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के तहत किरायेदारों के दावे की जांच - क्या यह तथ्यों की किसी विशेष स्थिति के अस्तित्व पर निर्भर करता है—सहायक कलेक्टर द्वारा दिया गया निर्णय-क्या न्यायिक समीक्षा के योग्य है।

10. . 1966 वर्ष. एल.जे. (पंजाब) 678.

खजान सिंह आदि बनाम दलीप सिंह (न्यायमूर्ति सोढ़ी)

आयोजित, पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 में यह कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत किरायेदारों के दावे की जांच के उद्देश्य से सहायक कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अस्तित्व पर निर्भर करेगा। तथ्यों की कोई विशेष स्थिति। की धारा 18 की उपधारा (1) में संदर्भित मामले। अधिनियम अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्तों का गठन नहीं करता है। इन मामलों को, किसी भी हद तक, उन तथ्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिन्हें सहायक कलेक्टर को पहले यह निर्धारित करना होगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि उसके पास अधिनियम की धारा io के तहत आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं। इन मामलों पर उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, चाहे सही हो या गलत, उनके अधिकार क्षेत्र में होगा और सिविल न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा। (पैरा 4)

की ओर से दूसरी अपील; जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत की डिक्री, दिनांक 20 वीं*फरवरी का दिन,* 1959,*सबजज की बात को पलटते हुए,* 1st *क्लास, रोहतक, दिनांक 17 जुलाई, 19^8 और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया।*

गंगा प्रशाद जैन और जी. सी.गर्ग, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए.

एम. एम.पुँच्ची , वकील, उत्तरदाताओं के लिए.

प्रलय

न्यायमूर्ति सोढ़ी -यह नियमित दूसरी अपील निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होती है।

1. खजान सिंह और जागे, वादी अपीलकर्ता, गांव मोखरा खेड़ी रोझ, तहसील गोहाना, जिला रोहतक में खसरा नंबर 5901, 5902 और 4214 के अनुसार 16 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि के मालिक थे। दलीप सिंह और भल्ले प्रतिवादियों ने दावा किया कि वे वादी के तहत किरायेदार थे और पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट की धारा 18 (2) के तहत सहायक कलेक्टर को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने उक्त जमीन खरीदने की इच्छा व्यक्त की। भूमि। उनका आरोप था कि वे यहां के किरायेदार हैं और यह मकान मालिकों के लिए आरक्षित क्षेत्र नहीं है। सहायक कलेक्टर ने वादी जमींदारों की आपत्तियों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि खसरा नंबर 5901/3595-96 और 4214 को प्रतिवादी दलीप सिंह और भल्ले ने जागे वादी से खरीदा हुआ माना जाएगा। रुपये के लिए खजान सिंह वादी से 1,450 और खसरा संख्या 5902/3592—3594 आदि रु. 2,100. सहायक कलेक्टर के समक्ष एक विवाद उठाया गया था कि क्या प्रतिवादी किरायेदारों ने 2 जनवरी, 1956 को आवेदन की तारीख पर कम से कम छह साल की अवधि के लिए किरायेदारी में शामिल भूमि पर लगातार कब्जा कर रखा था, जैसा कि अधिनियम की धारा 18 में परिकल्पित, सहायक कलेक्टर खसरा गिरदावरियों पर विचार करने और उनके सामने मौजूद सामग्री की सराहना करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादियों ने आवश्यक शर्तों को पूरा किया है, क्योंकि वे छह साल से अधिक समय से किरायेदार हैं और किसी भी आरक्षित क्षेत्र पर किरायेदार नहीं हैं। यह सुझाव नहीं दिया गया कि वादी के जमींदार छोटे जमींदार थे। जमींदारों द्वारा कलेक्टर के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसे 27 सितंबर, 1956 को खारिज कर दिया गया था और आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका का भी 4 फरवरी, 1957 को वही हश्र हुआ। आयुक्त का आदेश प्रदर्शित डी. 1 है। इस मामले का रिकॉर्ड. अधिनियम के तहत कार्य करने वाले सभी प्राधिकारियों ने प्रतिवादी किरायेदारों के पक्ष में पाया और सहायक कलेक्टर के निष्कर्षों से सहमत होते हुए माना कि किरायेदार जमींदारों के अनुमेय आरक्षित क्षेत्र से अधिक भूमि खरीदने के हकदार थे। जमींदार खजान सिंह और जगे ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष असफल होने पर 9 नवंबर, 1957 को इस आशय की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि सहायक कलेक्टर द्वारा 31 जुलाई, 1956 को पारित आदेश अधिकारों के खिलाफ अवैध, शून्य और अप्रभावी था। वादी जमींदारों के स्वामित्व के बारे में और खसरा नंबर 5902 में शामिल भूमि के पांच बीघे पुख्ता पर जमींदारों के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी

किरायेदारों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की, जो कि जमींदारों के अनुसार, उनके कब्जे में नहीं थी। बचाव पक्ष।

2. 5 प्रतिवादियों ने आरोपों से इनकार किया और दलील दी कि वे किरायेदारों के रूप में मुकदमे की भूमि पर वैध कब्जे में थे और अधिनियम की धारा 18 के तहत इसे खरीदने के हकदार थे। सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर भी आपत्ति उठाई गई और पक्षों की दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए-

1. क्या राजस्व अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन एवं कानून की दृष्टि से खराब है?
2. क्या सिविल न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है?
3. क्या वर्तमान वाद विबंधन के नियम द्वारा वर्जित है?
4. क्या विचाराधीन कार्य है *अधिकारातीत* संविधान का?
5. राहत। 1 . "-

वाद क्रमांक 1 का निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी पक्ष के पक्ष में किया गया। मुद्दा संख्या 2 के तहत, यह माना गया कि चूंकि राजस्व अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़े, इसलिए वह प्रतिवादियों और सिविल कोर्ट को कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं कर सकते थे।

खजान सिंह आदि *बनाम दलीप सिंह* (न्यायमूर्ति सोढ़ी)

मुकदमे की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र था, जो ट्रायल कोर्ट के अनुसार, अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित नहीं था। अंक संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादियों के विरुद्ध किया गया क्योंकि उनके द्वारा वादी के विरुद्ध रोक की किसी भी याचिका को उचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर रिपोर्ट की गई भगीरथ *Bhagirath* बनाम *पंजाब राज्य* (1), अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती और मुद्दे संख्या 1 से 4 पर निष्कर्षों के आधार पर, मुकदमे का फैसला सुनाया गया।

(3) प्रतिवादियों ने जिला न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष अपील की, जिन्होंने इसकी अनुमति दी और वादी के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सिविल कोर्ट के पास ऐसे मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो अधिनियम की धारा 25 द्वारा वर्जित था। जिला न्यायाधीश का विचार था कि ट्रायल कोर्ट के लिए इस आधार पर सहायक कलेक्टर के आदेश को रद्द करने की डिक्री देना संभव नहीं था कि निर्णय गलत था, जब यह नहीं दिखाया गया था कि सहायक कलेक्टर ने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया था। अत: वर्तमान द्वितीय अपील।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री गंगा पार्षद जैन का कहना है कि वादी अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा एलएफआर के तहत वाद भूमि खरीदने की अनुमति देने में सहायक कलेक्टर और उच्च राजस्व

अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र विभिन्न शर्तों पर निर्भर करता है, उनमें से एक यह है कि किरायेदारों को आवेदन की तारीख से पहले छह साल की अवधि के लिए भूमि का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा होना चाहिए था और ऐसे क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों में से किसी एक पर गलत निर्णय देकर, सहायक कलेक्टर क्षेत्राधिकार नहीं ले सकता है। दलील यह है कि जब किसी अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य पर गलत निष्कर्ष दिया जाता है तो प्राधिकारी के आदेश को अधिनियम के तहत पारित नहीं कहा जा सकता है, ताकि धारा 25 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया जा सके। मुझे डर है कि इस विवाद में कोई दम नहीं है। जिन्हें अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से पहले की स्थितियों या क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों के रूप में वर्णित किया जा रहा है, वे वास्तव में अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा तय किए गए मामले हैं। ये तथ्य के वे प्रश्न नहीं हैं जिनके अस्तित्व पर किसी विशेष कारण का निर्णय करने का अधिकार निर्भर करता है। पार्टियों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता माना जाता है और अधिनियम में यह कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है कि संपत्ति की जांच के उद्देश्य से सहायक कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाए।किरायेदार का दोषएसधारा 18 के तहत तथ्यों की किसी विशेष स्थिति के अस्तित्व पर निर्भर करेगा। अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में संदर्भित मामले अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थितियां नहीं बनाते हैं। उन्हें, किसी भी तरह से, तथ्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे सहायक कलेक्टर को पहले यह निर्धारित करना होगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि उसके पास अधिनियम की धारा 18 के तहत आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं। इन मसलों पर उनका दिया गया कोई भी फैसला, चाहे सही हो या गलत, उनका अधिकार क्षेत्र होगा. क्षेत्राधिकार और सिविल न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं। अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रोहतक ने तथ्य के सवालों पर अपील में बैठकर मामले में पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण अपनाया और यह भूल गए कि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया, और तथ्य के सवाल पर कहा कि वादी ने अपेक्षित अवधि के लिए मुकदमे की भूमि पर खुद को कब्जे में साबित कर दिया है। यह वही है जो करने की उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। जिला जज ने बहुत ही सही ढंग से अपील स्वीकार कर ली और मुकदमा खारिज कर दिया।

4. उपरोक्त कारणों से, मुझे अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती जिसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, हरियाणा